श्री राघवजी: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय चतुर्वेदी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जो विषय रखा है उससे मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए कश्मीर में, श्रीनगर में जो घटना घटी है उसकी निन्दा करता हूं। यह घटना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले वर्ष 6 विदेशी पर्यटक वहां सैर करने गए थे जो आज तक लौट कर नहीं आए हैं। उनका अपहरण हुआ है और हमारी सरकार उनको छुड़ाने में विफल रही है। ये पर्यटक जो 12 थे, उनमें से 6 मरे हुए लौटे और 6 जिन्दा लौटे हैं। ऐसी हालत में किस प्रकार से पर्यटन इस देश में बढ़ेगा? कश्मीर में श्रीनगर खासतौर से पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी परिथिति में वहां पर पर्यटक जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में मेरी मांग है कि केंद्रीय सरकार जो वहां अर्द्ध-सैनिक बल या सीमा सुरक्षा बल है, उनको पूरी छूट दे ताकि वहां पर आतंकवाद का सफाया हो जाए और कश्मीर में फिर से वही स्थिति प्राप्त हो जो पहले पर्यटन के मामले में प्राप्त थी।

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, कल जो हादसा कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में हुआ और उसमें जो 6 व्यक्ति, जो इस देश के नागरिक थे मारे गए, जिनकी वहां पर जघन्य हत्या हुई, उनके प्रति और उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी समवेदना प्रकट करते हुए सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं, कि कश्मीर में इस प्रकार के हादशे बहुत हो चुके हैं। हजारों लोग इस तरह से मारे जा चुके हैं। उनकी हत्यायें हो रही हैं और वहां पर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इतने लोगों के मरने के बाद भी क्या कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हम बिरयानी खायेंगी और मुर्ग-मुसल्लम की नीति का समर्थन करते रहेंगे? क्या हम उन लोगों के साथ हमेशा इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे...**(व्यवधान)**... मैं चाहता हूं कि सरकार को शठे शाठ्यम समाचरेत की नीति अपनानी चाहिए...**(व्यवधान)**...मैं चाहता हूं कि सरकार को...**(व्यवधान)**...उनसे निपटने का काम करना चाहिए और आतंकवादियों को किसी तरह का मौका नहीं दिया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**...क्या आप भारत के नागरिकों को इस तरह मरने देंगे?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please conclude now...*(Interruptions)*....

श्री रामदास अग्रवाल: मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि वह क्यों नहीं अपनी नीतियों को परिवर्तित करती? **(व्यवधान)** लोगों को सुरक्षित रखने का काम करती? यह उसकी जिम्मेदारी है, यह उसका दायित्व है, इसको निभाना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, one minute...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no. I am not allowing anybody ...*(Interruptions)*... Kindly conclude....*(Interruptions)*... Agarwalji, kindly conclude.

श्री रामदास अग्रवाल: क्या हत्याएं होती रहेंगी? **(व्यवधान)** क्या लोग मरते रहेंगे **(व्यवधान)** इस प्रकार के हज़ारों लोग हैं क्या उनके प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है। **व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Dr. Lakshmi Prasad has to speak on a different subject....*(Interruptions)*... I am not allowing anybody...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gurudas Das Gupta, I will not allow you...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, we want the Army to be there. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Dr. Lakshmi Prasad, please be brief because the Minister has to reply. Yesterday also, you raised this issue.

RE. ALMATTI DAM CONTROVERSY

डा० वाई लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठा रहा हूं यह बहुत छोटा है लेकिन बहुत नाजुक विषय है।...**(व्यवधान)** यह विषय आलामेटी डैम का है जिसकी ऊंचाई 40 फुट बढ़ाने का मामला है। लेकिन 40 फुट बढ़ाने से पूरा आन्ध्र रेगिस्तान बन जाएगा। हमारा अधिकार छीन लिया गया है। सन् 2000 तक बचे हुए पानी का अधिकार आन्ध्र प्रदेश का है लेकिन हमारा अधिकार छीन कर हम पर यह आरोप लगाते हैं और कर्नाटक विधान सभा में ऐसा बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश का कोई अधिकार नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के विधायक जो डैम देखने के लिए गये हैं उनको अरेस्ट करने का मामला भी वहां उठाया गया है। वहां यह भी कहा गया है कि आन्ध्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। विषय बहुत नाजुक है। **(व्यवधान)**

No, no. These are the extracts of the *Hindu*.

आन्ध्र प्रदेश में गर्मी फैल रही है और इस गर्मी के जन आन्दोलन का रूप धारण करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और केन्द्र से जल संसाधन इंजीनियर्स को वहां भेज कर आन्ध्र प्रदेश के प्रति न्याय करें, यह हमारी मांग है।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): One Member from your party has already spoken. Do you want the Minister to reply or not?...*(Interruptions)*.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I associate myself with him...*(Interruptions)*...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on this burning problem, although we had not given any notice for that. Sir, today both the Houses of the Karnataka legislature are sitting and a lot of agitation is going to take place. Sir, yesterday we mentioned this issue in the Special Mentions. Today, luckily our hon. Minister is here. Yesterday the hon. Prime Minister resloved the long-panding dispute of the Sardar Sarovar Dam concerning four States. My humble submission to the hon. Prime Minister is that he should convene a meeting of the Chief Ministers of Karnataka and Andhra Pradesh and try to resolve this issue. Sir, according to the bachawat Award, Andhra Pradesh has got the right to use it till 2000 A.D. Now, these people are raising the dam and nearly 400 TMC water is going to be stored in that, and that will affect nearly 34 lakh acres of land in Andhra Pradesh. Sir, this move will be responsible for any agitation that will take place. Provocative statements are being given in the State Assembly. They are dividing the people of Andhra and Karnataka.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister respond.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: It should not be forgotten that they are trying to divide the people of Andhra and Karnataka. I am cautioning that the integrity of the nation would be in danger if this sort of statements are given.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister respond...*(Interruptions)*...Mr. Minister, would you like to respond? ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHU MANI: (Tamil Nadu) Sir, 5 TMC water is not sufficient ....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no ...*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: (Kerala): Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, would you like to respond? ...*(Interruptions)*... This is the discussion between Karnataka and Andhra Pradesh. Mr. Muthu Mani, if you want to raise any issue, you give notice for that....*(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, it could be easily sorted out in the United Front's Co-ordination Committee, rather than wasting the time of the House....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, would you like to respond?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): उपसभाध्यक्ष, जी हम तो अपना ही दर्द आपसे कहेंगे। हमने कभी नहीं देखा था कि किसी मंत्री को हमारे साथी सदन में कहें कि खबरदार आगे मत बढ़ना, तुम बैठो देर तक। एक तरह से लगा कि आधा घंटा, 45 मिनट के लिए हम अंडर अरेस्ट हैं बाहर जब हम विरोधी पार्टी में थे तब कलक्टर या कप्तान कहता था कि इसके आगे जाओगे तो ठीक नहीं होगा, वहीं पर हम लोग बैठ जाते थे लेकिन मंत्री भी इतना कमज़ोर होता है जितना विरोधी दल के लोग हैं, आज [illegible]। लेकिन ये मित्र लोग हैं। प्यार में इतना दम होता है कि मंत्री नहीं, बड़े बड़े बादशाहों को भी बैठा दिया करता है और झुका दिया करता है। इन लोगों ने बहुत ही स्नेहपूर्ण

भाषा में कहा है कि बैठो हमारा दर्द सुनो। इन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। कोई भी उचित सूचना अगर आपके कार्यालय को आती है तो इस पर बहस की जा सकती है और उसका जवाब दूंगा समय पर। इतनी जल्दी, आम तौर से, शून्य काल में जो प्रश्न उठाए जाते हैं, मंत्री उनका जवाब नहीं देते हैं और उनको न कहा जाता है कि जरूर जवाब दो। अपने मित्रों से मैं कहूंगा कि इस मुद्दे को देखा जाएगा और वक्त आने पर इसका जवाब दे दिया जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now the House is adjourned till 2 o' clock. At 2 o' clock we will take up Special Mentions.

The House, then, adjoined at one minute past one of the clock for lunch.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) *in the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, I would like to take up the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Functioning of Cochin Shipyard

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Madam, Vice-Chairman, I would like to draw the attention of the Government of India to what is happening in a major public sector undertaking in Kerala, the Cochin Shipyard which is totally a Government of India-owned concern and which gives employment to thousands of persons inside and so many thousands of outsiders also in the ancillary industries. Now, over the years the ancillary industries have developed and they have been suppling spare parts etc. Unfortunately, because of the recent globalisation and corruption at the top with the kickbacks etc. a new situation has developed. The Chairman of the Cochin Shipyard I understand, has somehow got in even though he is not properly qualified. I understand one should have at least the rank of a Rear-Admiral. But even without that, he managed to become the CMD, Chairman and Managing Director. After that, corruption has spread in a very bid way. Previously they used to get the spare parts from the ancillary industries. Now, the fashion is to import everything from outside. Even nuts and bolts are being imported and, of course, with proper commission, kickbacks etc. As I have just mentioned here, the Shipyard wanted to import steel from British Steel, a foreign company and they required only 360 tons. They imported 3,000 tonnes and there is a great loss. The previous Chairman said that it is of substandard quality and it cannot be used. But the new Chairman and Managing Director thought it fit that it can be used. There are allegations about this change of the stand. The change took place when the new Chairman came and enjoyed the hospitality which was extended to him and his family in London by the foreign company. After that this import was sanctioned and more than three crores of rupees have been lost by the company. There is another one also. A giant crane had to be updated, the control system had to be updated. The foreign Multinational Co., ABB was asked to give the quotation. They gave a quotation for Rs. 92 lakhs. It was to be accepted. Suddenly, within two weeks it was changed and the agreement was signed for Rs. 106 lakhs. It is said that this Chairman's son was given employment by the ABB multi-national company in Sweden. This made all the difference. Similarly, even nuts and bolts are being imported from far off companies in Singapore and other multi-national companies. What is happening in Cochin Shipyard is a clear case of collusion between the corrupt bureaucracy and the corrupt politicians to the detriment of the national interest. It is not only a case where there is a great loss incurred by the Cochin Shipyard because of this. It also effects a large number of ancillary industries who are totally dependent upon the welfare or the coming up of the Cochin Shipyard. Therefore, there have been demands that the whole thing should be enquired into; the charges of